'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.07.2015
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: aicscst@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 16 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 जूलाई, 2015

भारत में बडे सुधार की आवश्यकता

जब जब सरकार एवं नेतृत्व विकास और बदलाव की शुरुआत करते हैं तो उस समय लोगों में आशा और उत्साह पैदा होता है लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, उसकी आलोचना भी शुरू हो जाती है। लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि वही इस कार्य को करेगी। हमारा समाज व्यक्तिवादी ज्यादा है और सामुदायिक कम है, इसलिए अपने निजी स्वार्थ में तो कुछ भी करने को तैयार रहता है। 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की कि देश को स्वच्छ बनाएं, इसको पार्टी से न जोड़ने की अपील की ताकि लोग इस कार्यक्रम को राजनीति से प्रेरित न समझें और अपने देश को भी दूसरे देशों की तरह स्वच्छ बनाएं। प्रधानमंत्री ने स्वयम हाथ में झाड़ू पकड़ी यह एक अप्रत्याशित बात थी। तब लाखो लोग झाड़ु पडकने के होड में आ गए। शुरुवात में ही एक संदेश गया कि सफाइ करना नीच कार्य नही है। इसके बावजूद भी देशवासी उस तरह से नही इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया जो कि हो जाना चाहिए था।

हाल में आस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में शाम को भारतीयों को सम्बोधन करने का मौका मिला और जब सवाल-जवाब का समय आया तो एक महानुभाव ने कहा कि भारत में

गंदगी तो अभी बनी ही है, मोदी जी ने क्या किया ? मुझे जवाब देना ही था तो उनसे पूछा कि भारत से आप आएं हैं तो यह भी जानते होगें कि सैकड़ों विश्वविद्यालय, लाखों कॉलेज और स्कूल तो हैं ही, साथ ही लेखक, पत्रकार, विद्वान एवं शोधकर्त्ता लाखों की संख्या में देश में हैं। एक तरह से भारी-भरकम शिक्षा व्यवस्था देश में है, उसने छात्रों एवं देशवासियों को एक बहुत ही छोटा पाठ नहीं पढ़ा सकी कि लोगों को स्वच्छ रहना चाहिए। जब इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था एक छोटी सी सीख नहीं दे सकी तो कमी उसकी है कि प्रधानमंत्री की ?क्या प्रधानमंत्री को देश को स्वच्छ बनाने की अपील करनी चाहिए थी ?इसलिए किया कि देश के विकास में इसकी बड़ी आवश्यकता है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ने इस कार्य को किया होता तो सरकार का समय और संसाधन किसी और कार्य में लगता। उन्हें प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहिए था बजाय कि यह कहना कि कुछ नहीं हुआ है। इस जवाब के सामने महानुभाव निरुत्तर हो गए।

सरकारी नौकरी सबसे अच्छी और उसको प्राप्त करने के लिए करोड़ों युवा अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं। दूसरी तरफ सरकारी हास्पिटल, रेल, बस, कार्यालय, काम-काज से परहेज। केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को समय पर आने और जाने के लिए बायोमैट्रिक व्यवस्था की तो उससे तमाम लोग नाराज हो गए। पहले कि जो आदत पड़ी थी की देर से आना और जल्दी जाना, इससे कुछ के निजि जीवन में कष्ट होने लगा। इसका थोड़ा-बहुत खामियाजा दिल्ली के चुनावों में भी भुगतना पड़ा। एक डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस मैनेजर जो करोड़ों आराम से बड़ी कंपनियों में कमा सकते हैं, फिर भी क्यों नौकरशाही में घुसने को वरीयता देते हैं। आखिर में ऐसा क्यों? समझना मुश्किल नहीं है। सरकारी नौकरी में काम कम करना पड़ता है। देर से आए और पहले चले जाऐ तो भी काम चलता रहता है। तमाम मलाई दार विभागों का फायदा भी है। इशारों में समझाना उचित होगा वरना सच्चाई कई बार अप्रिय होती है।

भारतीय समाज के लोगों की एक ऐसी मानसिकता बन गयी है कि सबकुछ सरकार करे। सवाल यह पैदा होता है कि सरकार कौन सी वस्तु या चिड़िया है, वह तो लोगों से ही बनती और चलती है। जो प्रतिनिधि होते हैं, वे नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन नियम-कानून मानना और सरकारी घोषणाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करना एवं कराना आदि सभी लोगों पर निर्भर करता है। जनता के हित में सरकार के कुछ कार्यक्रम जैसे - स्वच्छता, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जनधन योजना, स्किल इंडिया आदि यदि ठीक से लागू हो जाए तो भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह उसी तरह हो सकता है जैसे दुसरें देशों में समय समय पर परिवर्तन और क्रांति से हुए है। बिना लोगों के सहयोग के यह संभव हो नहीं सकता।

देश में चाहे जितना संसाधन, उपयुक्त जलवायु, उर्वरा भूमि हो, फिर भी विकस नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा अगर योगदान विकास और अच्छा समाज बनाने में कोई दे सकता है, तो वहां के नागरिक। न्यूजीलैंड एवं आस्ट्रेलिया जैसे देश भारत की दृष्टि से उतने अनुकूल स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्होंने तरक्की का झंडा गाड़ दिया। आस्ट्रेलिया में 1770 के आस-पास इंग्लैंड एवं यूरोप से काला पानी की सजा काटने वाले आए और 200 वर्ष के अंतराल में किस ऊंचाई पर पहुंच गए, जानना मुश्किल नहीं है। हम लगभग पांच हजार वर्ष में देश को उतना आगे नहीं ले जा सके। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि हमारी आबादी की समस्या है तो उसका भी जवाब है कि जापान और कोरिया जैसे ऐसे देश हैं, जहां आबादी का घनत्व भी ज्यादा है, जमीन भी समतल नहीं है और पहाड़ ही पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, फिर भी उन्होंने क्या मुकाम प्राप्त किया है, किसी से छुपा नहीं है। देश का निर्माण नागरिक करते हैं।

भारतीय समाज में क्रांति की आवश्यकता और वह सामाजिक क्षेत्र में। जिस तरह से यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी तक नवजागरण हुआ, जिसमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला, उसी प्रकार के नवजागरण की आवश्यकता भारत को भी है। यह नवजागरण इटली से उठा और पूरे यूरोप को आगोश में लिया। यूरोप ने दूसरा आंदोलन भी देखा जो 16वीं शताब्दी में उभरा जो सुधारवाद के नाम से जाना जाता है। 1860 तक जापान दुनिया के और समाजों से कटा हुआ था और सोचा जा सकता है कि वह तमाम ज्ञान/ विज्ञान और तकनिक से वंचित और पिछड़ा रहा होगा लेकिन मेजी क्रांति ने जापान को बदलकर रख दिया। जापान में 1868 और 1872 के बीच उत्पादन 1026 टन और निर्यात 646 था, वह 1909 और 1914 के बीच बढ़कर 12,460 और 9,462 हो गया। मेजी आंदोलन के पीछे अमेरिकन प्रगति भी थी। जब जापानियों को पता लगा कि अमेरिका कितना आगे तो उनमें स्पर्धा हो गई कि हमे जो भी बलीदान करना होगा, करेगें और उसे विकास को कौन नही जानता। मेजी का मतलब प्रबुद्ध प्रशासन होता है और पूर्वी एवं पारंपरिक मूल्यों के साथ-साथ आधुनिकता का मिश्रण। इसी तरह से चीन में सांस्कृतिक क्रांति जो 1966 में शुरु हुई, उसने वहां के लोगों को मानसिक परिवर्तन में बड़ा योगदान दिया। हालांकि सत्ता की जोर-जर्बदस्ती का इस्तेमाल भी गलत किया गया।

सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यदि उने लागू कर दिया तो भारत में बड़ा आंदोलन आ सकता है। सरकारे कम ही क्रांतिकारी कदम उठाती है, इस लिए यह अभियान सराहनीय है। सुधार और क्रांति कि पहल समाज कि ओर से कही ज्यादा होता है। स्वच्छ भारत अभियान जैसा समाज के आहवान पर होना चाहिए था , लेकिन किया गया सरकार कि ओर से। अगर समाज भाग लेकर सफल नही बनाता तो एक ऐतिहासिक भूल होगी। लोगों से अपील है की इस विचार को किसी पार्टी से न जोड़े क्योंकि मैं भाजपा का सांसद भी हूं।

– डॉ. उदित राज
सांसद एवं
राष्ट्रीय अध्यक्ष
अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों
का अखिल भारतीय परिसंघ

+++

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

नेशनल एस.सी.एस.टी.ओबीसी स्टूडेन्टस् एण्ड युथ फ्रन्ट का अर्जेडा

नेशनल एस.सी.,एस.टी., ओबीसी स्टूडेन्टस् एण्ड युथ फ्रन्ट (नसोसवायएफ) का गठन 28 अप्रैल 2013 के नागपूर की दीक्षाभूमि पर डॉ. उदित राज जी की उपस्थिति में किया । इस संगठन का मातृ संगठन अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ है। डॉ. उदित राज जी इस संगठन के मुख्य मार्गदर्शक एवम् नेतृत्व के रूप में कार्यरत है।

इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जाति विहीन समता मुलक समाज का निर्माण करना है। महात्मा फुले, शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, पेरियार, डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर इन महापुरुषों के विचारों को आधार मानते हुए छात्र एवं युवाओं के संगठन से सामाजिक परिवर्तन लाना है। सदियों से देश में दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्र एवं युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करके अपने शिक्षा, रोजगार, भागीदारी और न्याय अधिकार के लिए राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना नसोसवायएफ का उद्देश्य है।

नसोसवायएफ युवा एवं छात्रों का अम्बेडकरवादी आंदोलन है।

नेशनल एस.सी.एस.टी.ओबीसी स्टूडेन्टस् एण्ड युथ फ्रन्ट (नसोसवायएफ) की जरूरत क्यों?

देश में दलित, आदिवासी, ओबीसी छात्र और युवाओं के स्थानीय स्तर पर काम करने वाले अनेक संगठन है। इन संगठनों का कार्यक्षेत्र जिला एवं विश्वविद्यालय तक ही सीमित हैं। इसलिए दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्र एवं युवाओं की ताकत बिखरी हुई है। इसी कारण आजादी के बाद आज तक दलित, आदिवासी, ओबीसी का कोई राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा नहीं हो सका इन वर्गो का शोषण देश में आज भी हो रहा है। आज भी दलित, आदिवासी देहातो में अछूत की जिन्दगी जी रहे है। आज भी दलित, आदिवासियों के उपर होने वाले जुल्म एवं अत्याचार में कमी नहीं है। शिक्षा और रोजगार में दलित, आदिवासी, ओबीसी की भागीदारी ना के बराबर है। देश आजाद हुआ मगर दलित, आदिवासी आज भी गुलामी की जिन्दगी जी रहे है। शहरों की जुग्गी झोपडियों में दलित ही बसा हैं। आज भी गाँव, शहरों की गन्दगी साफ करने वाले 100% दलित ही हैं। हजारों सालों से चला आ रहा ये शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये कैसी आजादी है दोस्तों ये वास्तव आपको मालूम है। आप शिक्षित युवा और छात्र अपने नेताओं को इस परिस्थिति का जिम्मेदार मानकर अपनी जिम्मेदारी टालने की कोशिश कर रहे हैं। भाषण और बोलबच्चन, गुस्सा और अपने नेताओं को गाली देकर परिस्थिति में बदलाव नहीं आ सकता।

जातीय शोषण के खिलाफ छात्र और युवक कृतीपूर्ण संघर्ष करे और अपनी जिम्मेदारी उठाकर नवपरिवर्तन के लिए तैयार रहें। आज तक अम्बेडकरवादी विचारों को आधार मानने वाला दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्र एवं युवा का कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था। इसलिए हमारे छात्र और युवा अन्य संगठनों में कार्य करते थे। साम्यवादी, समाजवादी, गांधीवादी, लोहियावादी छात्र एवं युवा संगठन शोषण की बात करते है। मगर जातीय शोषण पर चुप्पी रखते है। वर्गीय शोषण के आड़े जातीय शोषण का ये संगठन समर्थन करते है। इस संगठनों की ताकत हमारे ही छात्र एवं युवा होते है। मगर इन संगठनों ने दलित, आदिवासी और ओबीसी के सामाजिक न्याय के लिए कभी आंदोलन खड़ा नहीं किया। हमारे छात्रों की ताकत हमारे ही खिलाफ इन संगठनों ने लगाई है। ऐसी परिस्थितियों में दलित, आदिवासी, ओबीसी छात्र एवं युवाओं के राष्ट्रीय संगठन की जरूरत थी।

भूमण्डलीकरण, निजीकरण के दौर में जाति व्यवस्था अधिक सक्रिय होती जा रही है। दलित अधिक दलित, आदिवासी बेघर और गरीब हो रहा है। निजीकरण के माध्यम से सरकारी नौकरियाँ और शिक्षा संस्थानों से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इस निजीकरण के माध्यम से फिर से दलित, आदिवासियों को गुलाम और बेबस बनाने की तैयारी जोरशोर से की जा रही है। इसके खिलाफ दलित, आदिवासी, ओबीसी छात्र एवं युवा ही एक मजबूत आंदोलन खड़ा कर सकते है। वो ही इस देश में सम्यक क्रांति ला सकते हैं। यह विश्वास लेकर ही हमने नेशनल एस.सी., एस.टी., ओबीसी स्टूडेन्टस् एण्ड युथ फ्रन्ट (नसोसवायएफ) का गठन किया है। हमारे छात्र एवं युवा फुले, अम्बेडकर, पेरियार, बिरसामुंडा के विचारों पर देश के नवनिर्माण करने के लिए दलित, आदिवासियों के दमन और शोषण के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करेंगे। हमारे सामाजिक न्याय अधिकार और देश में अपनी भागीदारी के लिए नेशनल एस.सी., एस.टी., ओबीसी स्टूडेन्टस् एण्ड युथ फ्रन्ट (नसोसवायएफ) की जरूरत है।

नसोसवायएफ के उद्देश्य :

1. जातिविहीन समतामूलक समाज का निर्माण करना : भारतीय समाज व्यवस्था जाति पर आधारित है। ये विशमतावादी समाजव्यवस्था इन्सान को गुलाम बनाने वाली व्यवस्था है। इन्सान को मानवीय अधिकार से वंचित रखने वाली इस जाति व्यवस्था को खत्म किए बगैर देश में समता मूलक समाज का निर्माण असंभव है। हम बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर आधारित जातिविहीन समतामूलक का निर्माण करना चाहते है।

2. सामाजिक न्याय और समान अवसर : देश में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्गो का शोषण और दमन जाति के आधार पर हजारों साल से हो रहा है। इन्हे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। इसलिए उनका सामाजिक, आर्थिक विकास नहीं होपाया। भारतीय संविधान में दलित, आदिवासी और ओबीसी को सामाजिक न्याय एंव समान अवसर के लिए षिक्षा, नौकरियों में आरक्षण दिया है। मगर तथाकथित सर्वण इसका विरोध कर रहे है। दलित, आदिवासी और ओबीसी के सामाजिक न्याय एवं समान अवसर के लिए नसोसवायएफ संघर्षरत है। दलित, आदिवासी, ओबीसी को सभी क्षेत्र में समान भागीदारी नहीं मिलती तब तक सामाजिक न्याय संभव नहीं है।

3. समान और अनिवार्य शिक्षा : सदियों से दलित, आदिवासी, ओबीसी को शिक्षा की पाबंदी थी। महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष से आज दलित, आदिवासी और ओबीसी को शिक्षा का अधिकार मिला है। मगर आज शिक्षा क्षेत्र में विशमतावादी व्यवस्था का निर्माण हुआ है। दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्र सरकारी स्कूल और विद्यालयों में पढ़ रहे है। तो सवर्ण, अमीर छात्र निजी स्कूल और विश्वविद्यालयों में शिक्षा ले रहे है। सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षक और शिक्षा के संसाधन निजी स्कूलों की तुलना में बहुत ही कम है। गरीब दलित, आदिवासी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। जहाँ शिक्षा का कोई माहौल नहीं है। सरकार भी सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दे रही है। इससे शिक्षा में विशमतावाद बढ़ रहा है। अच्छी शिक्षा निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में दी जा रही है और निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों को ही नौकरियों के अवसर प्राप्त हो रहे है। हम विशमतावादी शिक्षा व्यवस्था का विरोध करते है। सबको समान और अनिवार्य शिक्षा की मांग करते है। जहाँ गरीब और अमीर एक ही स्कूल, विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़े, दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों को जहाँ समान अवसर अपनी काबिलियत दिखाने के लिए मिले।

4. दबाव गुट का कार्य : छात्र एवं युवा संगठन ही दुनिया के सबसे बड़े दबाव गुट माने जाते है। दुनिया में जितनी क्रांतिया हुई है। वो छात्र और युवकों की बदौलत है। भारत में दलित, आदिवासियों के शोषण और दमन के खिलाफ नसोसवायएफ एक दबाव गुट का कार्य करेगा।

5. समतावादी महापुरुषों के विचारों का प्रचार-प्रसार : हम नसोसवायएफ के माध्यम से भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, महात्मा फुले, पेरियार, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा और डॉ.अम्बेडकर के समतावादी विचारों का छात्र एवं युवकों के अंदर प्रचार और प्रसार करने का काम नसोसवायएफ करेगा।

6. सांस्कृतिक बदलाव : जातिवादी दमनकारी सांस्कृति का हम विरोध करते है और नई विकासवादी संस्कृति का निर्माण करना चाहते है। कला, साहित्य, त्यौहार, संगीत, धर्म, रितीरिवाज इन सभी में समतावादी संस्कृति का निर्माण नसोसवायएफ के माध्यम से करना चाहते है।

7. शिक्षा, अर्थनीति, राजनीति में बदलाव : शिक्षा, अर्थनीति, राजनीति देश के विशिष्ट उच्च जाति के सवर्ण के हाथों में होने के कारण उन्होंने सिर्फ अपने जाति के लोगों का विकास किया है। ना की देश का इस व्यवस्था का दलित, अदिवासी को हिस्सा बनने ही नहीं दिया। नसोसवायएफ शिक्षा, राजनीति, अर्थनीति में अपने आंदोलन से बदलाव लाना चाहता है।

8. पुरुषवादी सोच का विरोध : नसोसवायएफ स्त्री-पुरुष समानता का पुरस्कार करता है। हम स्त्री-पुरुष को समान मानते है। स्त्री शोषण और दमन का हम विरोध करते हैं। हम जानते है। सर्वण स्त्री दलित, आदिवासी स्त्री का जातिगत शोषण और दमन करती है। और देश के स्त्री-पुरुष समानतावादी विचार रखने वाले सर्वण लोग दलित स्त्री पर हुए अन्याय और अत्याचार को गंभीरता से नहीं लेते है। इसलिए हम स्त्री शोषण के खिलाफ है। मगर संघर्ष में दलित, आदिवासी स्त्रीयों के शोषण को ही प्राथमिकता देंगे क्यों कि वो जाति और लिंग इस दुगुने शोषण को सह रही है।

नसोसवायएफ संगठन की माँगे :

1. निजी क्षेत्र में आरक्षण : निजी क्षेत्र में आरक्षण यह नसोसवायएफ की मुख्य माँग है। निजीकरण से सरकारी क्षेत्र खत्म किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र खत्म होने से आरक्षण खत्म हो रहा है। सरकारी क्षेत्र के बगैर दलित, आदिवासी, ओबीसी की भागीदारी किसी और क्षेत्र में नहीं है। सरकारी क्षेत्र में आरक्षण से ही हमारी भागीदारी निष्चित थी। मगर आज निजीकरण से सरकारी क्षेत्र समाप्त हो रहा है तो हमारी भागीदारी भी समाप्त हो रही है। विश्व के 50 देशों में सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर निजी और सरकारी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाता है। तो भारत में भी सामाजिक पिछडेपन के आधार पर निजी क्षेत्र में आरक्षण देना होगा, नहीं तो दलित-आदिवासी, ओबीसी की गुलामी निश्चित है।

2. समान और अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया जाए।

3. भारत सरकार छात्रवृत्ति महंगाई निर्देशांक से जोड़ दिया जाए।

4. दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों के लिए तहसील एवं जिला स्तर पर छात्रवास का निर्माण किया जाए।

5. शिक्षित बेरोजगार को काबिलियत के आधार पर रोजगार दिया जाए नहीं तो बेरोजगार भत्ता दिया जाए।

6. ओबीसी के लिए मंडल आयोग पूरी तरह से लागू किया जाए।

7. एस.सी.,एस.टी.,ओबीसी का बैकलॉग तुरन्त पुरा किया जाए।

8. देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तय की जाए।

9. धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाए।

10. भारत सरकार छात्रवृत्ति के लिए देश में एक ही कानून और नियम बनाये जाये

11. छात्र राजनीति के लिए सभी राज्यों मे लिंगदोह कमेटी की शिफारिशें लागू की जाए।

12. फुले, डॉ.अम्बेडकर, पेरियार इनके विचारों और जीवन पर आधारित पाठ्यक्रम बनाये जाए।

13. 3 जनवरी सावित्री बाई फुले की जयन्ती को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाए।

14. विद्यालय और विश्वविद्यालय की खेल प्रतियोगिता में दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्र को आरक्षण दिया जाए।

15. सभी स्कूलों और महाविद्यालय के शिक्षकों की भर्ती केन्द्रीय भर्ती प्रक्रिया से की जाए।

यह और अन्य मांगों को लेकर 'नसोसवायएफ' संघर्ष करेगा। नेशनल एस.सी.,एस.टी.,ओबीसी स्टूडेन्टस् एण्ड युथ फ्रन्ट (नसोसवायएफ) देश के सभी राज्यों में कार्य करने वाला पहला राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन का मातृ संगठन की जिम्मेदारी अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ पर है। डॉ.उदित राज जी के नेतृत्व में परिसंघ पिछले पन्द्रह सालों से निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग लेकर देश में संघर्ष कर रहे है। डॉ.उदित राज एक सच्चे अम्बेडकरवादी नेता है। जो सड़क के आंदोलन में भरोसा रखते है। और उसका कृतीपूर्ण समर्थन भी करते है। हम ऐसे ही नेता को इस संगठन का मार्गदर्शक मानते है।

नेशनल एस.सी.,एस.टी.,ओबीसी स्टूडेन्टस् एण्ड यूथ फ्रन्ट (नसोसवायएफ) निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग लेकर लाखों छात्र एवं युवाओं को संगठित करके आंदोलन कर रहा है। यह आंदोलन देश में दलित, आदिवासी और ओबीसी की भागीदारी निश्चित करेगा। इसके बगैर हमारे पास कोई जरिया नहीं है। लडेंगे नहीं तो गुलाम बनेंगे गरीब और बेबस की जिन्दगी जियेंगे। इसलिए यह संघर्ष हमारी आने वाली पीढ़ी (नस्लों) को आजादी के लिए है। हमारे न्याय और अधिकार के लिए है। हमारे मानव पद प्राप्त करने के लिए है।

नेशनल एस.सी.,एस.टी.,ओबीसी स्टूडेन्टस् एण्ड यूथ फ्रन्ट (नसोसवायएफ) का सदस्यता शुल्क 10 रू. है। आप सभी साथियों से हम अपील करते है इस आंदोलन का हिस्सा बने, संगठन के सदस्य बने और इस लड़ाई को मजबूत करें।

– डी. हर्षवर्धन
राष्ट्रीय अध्यक्ष
(नसोसवायएफ)

हम का लक्ष्य:आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी का खात्मा

बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के साथ न केवल अच्छे मैनेजर्स की टीम है बल्कि नेपथ्य में सशक्त आयोजक-प्रायोजक भी हैं, यह बात 24 जून को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में फिर साबित हो गयी, जहां 'हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्यूलर का पहला राष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित हुआ। मुझे 5-6 दिन पहले लखनऊ में रहने के दौरान ही इस सम्मलेन के आहूत होने की जानकारी मिली थी। एकला चलो की घोषणा से पीछे हटकर आगामी बिहार बिधानसभा चुनाव में राजग के साथ जाने का अप्रिय निर्णय लेने के बाद मांझी की स्थिति में क्या बदलाव आया है, इसे निकट से देखने दृसमझने के लिए ही मैं 23 जून को ही दिल्ली आ गया और अगले दिन हम सम्मलेन में पहुँच गए। आनन-फानन में आयोजित इस सम्मलेन में 'हम' की टोपी लगाए लोगों की भारी उपस्थिति मुझे सुखद आश्चर्य में डाल दी। मेरा धारणा थी कि बिहार में जगह-जगह प्रचंड भीड़ पाने वाले मांझी साहब अंततः राष्ट्रीय राजधानी में बिना किसी विशेष तैयारी के आयोजित सम्मेजन में भीड़ के लिहाज से भारी मायूसी का सामना करना पड़ेगा, पर वैसा हुआ नहीं। स्टेडियम 80-85 प्रतिशत भरा था और लोगों में भारी उत्साह था। जब भी समर्थकों का कोई ग्रुप स्टेडियम में प्रवेश करता, मांझी जिंदाबाद का इतना भारी शोर होता कि हमें गरदन घुमाकर देखने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता. बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर वहां के नेताओं में शक्ति प्रदर्शन की होड़ शुरु हो गयी है। विशेषकर राजग के सहयोगी दल पटना में सभा-सम्मलेन कर गठबंधन में अधिक से सीटें पाने व अपनी पार्टी के नेता को सीएम का दावेदार बनाने के लिए लिए मुस्तैद हो गए हैं। किन्तु चार महीने पहले गठित 'हम' ने पटना के बजाय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपनी ताकत आजमाने का चौकाने वाला निर्णय लिया। मेरी सोच थी कि चूँकि दिल्ली में शायद 'हम' का संगठन मजबूती से नहीं खड़ा हुआ है, इसलिए मांझी को यहाँ निराशा का सामना करना पड़ सकता है। किन्तु मेरा कयास गलत निकला और 'हम' के खाते में विरोधियों को खौफजदा करने लायक एक और सफल आयोजन दर्ज हो गया। मैंने इसके पहले मांझी साहब को 13 मार्च को जेएनयू और 18 अप्रैल को 1, अणे मार्ग में बुद्धिजीवियों और छात्रों को संबोधित करते सुना था, किन्तु हम का कोई सम्मलेन नहीं देखा था, इसलिए यह अनुमान भी नहीं लगा पाया था कि उनके पीछे कितने और कैसे नेता हैं। किन्तु ताल कटोरा स्टेडियम में नेताओं की जो भीड़ देखा, उसे देखकर यह मान जाना पड़ा कि १२ नवम्बर 2014 को नए अवतार उभरे मांझी ने अल्पकाल में बहुत कुछ अर्जित कर लिया है।

देवेन्द्र प्रसाद यादव, महाचंद्र प्रसाद सिंह, शकुनी चौधरी, नरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश पासवान, सम्राट चौधरी, रविन्द्र मिश्र, नीतीश मिश्र, अजित कुमार, पूनम देवी, डॉ.जगदीश शर्मा ,विनय बिहारी व अन्य दर्जनों नेताओं, जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, की मंच पर उपस्थिति बता रही थी कि बिहार में मांझी के रूप में एक नयी राजनीतिक शक्ति का उदय हो चुका है। नेताओं की भारी-भरकम भीड़ की खासियत यह थी कि सभी ही मजबूती से मांझी के साथ खड़े दिखे। यह देखकर कोई भी अचंभित हो सकता है कि अधिकांश नेता, जिनमें कई दशकों से मंत्री, विधायक या सांसद रह चुके हैं, जोर गले से यह दावा कर रहे थे कि उन्होंने अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में मांझी जैसा सच्चा व विजिनरी नेता नहीं देखा। दावा सबका यह भी था कि मुख्यमंत्री के रूप में मांझी ने जो ढेरों फैसले लिए, उनमें उन 34 फैसलों, का मुकाबला आजाद भारत का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, जिन्हें नीतीश सरकार ने खारिज कर दिया है। 24 जून के सम्मलेन से यह तय हो गया कि मांझी को अपने नेताओं का जैसा अपार समर्थन प्राप्त है, वह आज की तारीख में विरले ही किसी और को नसीब होगा।

इस सम्मलेन में राजनीतिक प्रस्ताव के साथ सांगठनिक प्रस्ताव भी पारित हुआ जिसके तहत हम को पूरे देश खड़ा करने का संकल्प लिया गया। महाराष्ट्र, कर्णाटक, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा इत्यादि से आए लोगों ने अपने-अपने राज्यों में हम को फैलाने का आश्वासन दिया। लगभग 12 बजे शुरु हुए सम्मलेन में मांझी 2-40 पर माइक थामे और ठीक 3-39 पर अपनी वाणी पर विराम लगाए। उन्होंने शुरु में कहा, आज से सौ साल पहले किताबों में एक नारा उछला था, दुनिया के मजदूरों एक हो। आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हिन्दुस्तान स्तर बिहार से हम नारा दे रहे हैं, दुनिया के गरीबों एक हो। 67 साल की आजादी में देश पर हुकूमत करने वाले बताएं, गरीबी कम हुई है या बढ़ी है। एक घंटे के उनके संबोधन का फोकस मुख्यतः उन 34 फैसलों पर था, जिसे नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद खारिज कर दिए। 'हम' इन्ही फैसलों को लेकर मतदातों के बीच जायेगा,यह बात इस सम्मलेन में उन्होंने फिर दोहराया। मांझी के मुख्यमंत्रित्व काल में लिए गए फैसलों पर ही 'हम' की सारी उम्मीदें टिकी हैं,शायद इसलिए ही सबके भाषण का फोकस न सिर्फ इन पर था,बल्कि अवाम को इससे अवगत करने के लिए 10 पृष्ठ की मल्टी-कलर वाली एक मैगजीन साइज की पुस्तिका भी लोगों के मध्य बांटी गयी जिसमें 'प्रमुख नीतिगत निर्णय' और 'राज्य स्तरीय कार्य' शीर्षक से मांझी के मुख्यमंत्रित्व काल के कार्यों की झलक प्रस्तुत की गयी है। पुस्तिका की उद्देश्यिका में कहा गया है।

विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत राष्ट्र विश्व में एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक राष्ट्र का प्रतीक बन चुका है। इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु भारतीय संविधान के रचयिता एवं महान शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के अथक प्रयासों के बदौलत आज राजा अपने माता रानी के पेट से नहीं वरना एक चाय पिलानेवाले व्यक्तित्व के गर्भ से निकलता है। परन्तु दुःख की बात है कि आजादी के 67 वर्ष बाद भी आज तक भारत राष्ट्र में समता मूलक समाज की स्थापना पूर्णरूप से नहीं हो पाई है। अमीर और अमीर होते जा रहे है, गरीब और गरीब होत जा रहे है। विशेषकर आज का दलित समाज भीषण पीड़ा और प्रताड़ना की जिंदगी झेल रहा है तथा वो राष्ट्र के विकास में अपनी सहभागिता ढूंढता है तो उसे मायूसी दीखती है और उसे विषमता, शोषण एवं जुल्म सहने पड़ते हैं। किसी राष्ट्र-राज्य को एक लोकतंत्रता में यदि बने रहना है, बढ़ना है तो भीषण सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी से निजात पाना होगा। न्यायालय, पुलिस और मीडिया ने गरीबों के हित संरक्षण के दायित्व का निर्वहन किया ही नहीं वरना उन्हें हासिये पर ला रखा है। यदि संविधान के प्रावधानों को इमानदारी से लागू किया जाय, राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को बचाया जाय, भूमि सुधार किया जाय, शिक्षा-स्वस्थ्य और निजी स्वायत संस्थाओं का चरित्र लोकतांत्रिक बने, उनमें दलितों एवं गरीबों को उचित भागीदारी मिले तो व्यापार, उद्योग और तकनीकी क्षेत्रों में एक संतुलित विकास की स्वस्थ्य सकारात्मक स्पर्धा शुरू हो सकती है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ती के लिए यथा गरीबों, दलितों, असहायों, वृद्धों, महिलाओं एवं अन्य वर्गो के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से अपनी सरकार के अंतिम 12 दिनों में स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के दौरान उन्होंने वैसे नीतिगत फैसले लिए जो सामाजिक परिवर्तन में दूरगामी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। उद्देश्यिका बतलाती है कि 'हम' का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी का खात्मा है, जिसके लिए यह उद्योग-व्यापार, मीडिया-न्यायपालिका सहित तमाम संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण करना चाहता है। मांझी के कार्यकाल के 34 फैसलों में संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण के बीज है, इसलिए 'हम' के नेता उत्साह से भरे हुए हैं।

– एच. एल. दुसाध

+++

भारत में मृत्युदंड सिर्फ गरीब और दलित के लिए

फांसी आमतौर पर गरीबों और दलितों को ही होने की बात पर गौर करते हुए विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एपी शाह ने कहा है कि देश में मौत की सजा पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शाह ने कहा, आम तौर पर गरीब और दलित ही मौत की सजा पाते हैं। मृत्युदंड गरीबों को अधिक मिलता है। उन्होंने कहा, व्यवस्था में विसंगतियां हैं और अपराध के लिए दंडित करने के वैकल्पिक मॉडल की आवश्यकता है और भारत में मृत्युदंड पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की भी जरूरत है।

न्यायमूर्ति शाह श्यूनिवर्सल एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टीः ए ह्यूमन राइट्स इंपरेटिव विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन विधि आयोग ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किया।

ए.पी. शाह, पूर्व न्यायाधीश
दिल्ली हायकोर्ट

+++

जाति के अधार पर किया जाता है परमोशन

रांची। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में तीन स्वर्ण पदक जीतने वाली झारखंड पुलिस की सब इंस्पेक्टर झानू हंसदा ने अपने विभाग पर सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके विभाग में जाति के आधार प्रमोशन दिया जाता है। हाल ही अमेरिका में खत्म हुई वर्ल्ड पुलिस गेम्स की पदक विजेता झानू अपने सम्मान समारोह में ही सबके सामने फूट फूटकर रो पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि वे झारखंड पुलिस विभाग में जाति के आधार पर होने वाली पोस्टिंग और प्रमोशन की राजनीति का शिकार हुई हैं।

2004 में स्पोर्ट्स कोटे में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुई झानू ने यह सनसनीखेज आरोप झारखंड पुलिस के एडीजी रेजी डुंगडुंग समेत कई सीनियर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में लगाए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) ने अब तक सैकड़ों पदक जीत चुकी झानू का सम्मान समारोह आयोजित किया था। इस समारोह में झानू ने कहा- झारखंड में अगड़ी जाति वालों का दबदबा है। इसी वजह से मुझे कई कोशिशों के बावजूद अब तक प्रमोशन नहीं मिल पाया है।

झानू अभी जमशेदपुर रेल पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थ है। यदि उनका नियमों के अनुसार प्रमोशन हुआ होता तो वे अभी तक डीएसपी बन चुकी होती। पुलिस की विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया है। झानू की यह हालत देखकर झारखंड पुलिस के एडीजी रेजी डुंगडुंग ने भी स्वीकारा कि इस तीरंदाज के साथ भेदभाव हुआ है।

+++

नसोसवायएफ का दलित-आदिवासीयों को मानव पद प्राप्ती का संघर्ष

भारतीय समाज व्यवस्था विभक्त विविधता भरी जाति व्यवस्था पर अधारीत है। इस जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज बीकरा हुआ और कमजोर हमेशा ही दिखाई देता हैं। जातिय करण में बडे पैमाने पर उच्च-निच का भेद-भाव है और हर एक जाति एक-दूसरे जाति से दुरी बनाकर रहते है। उची जातियों जाति व्यवस्था के सबसे निचले दलित जातियों का दमण और शोषण हजारो साल से करते आ रहे है। दलित जातियों को ना धार्मिक, शिक्षा, आर्थिक और राजनितीक आधिकारों से आज तक वंचित रखा हैं। यह गुलामी दूनिया की सबसे भयावक गुलामी मानी जाती है। जो पिढी दर पिढी चलती आ रही हैं। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकरने जाति व्यवस्था की पराभाव संज्ञा करते वक्त कहा था, जाति का बंदिस्त वर्ग हैं यह ऐसी इमारत है जिसमें सिडिया नही हैं। एक जाति दूसरे जाति के साथ मेल-जोल और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सम्बंध प्रस्थापित नही कर सकती । वैसे जाति व्यवस्था एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है और एक समस्या भी है।

भारतीय इतीहास में उत्तवैदिक काल से ही वर्ग व्यवस्था से भारतीय समाज को बाटा गाया है। पहले तीन वर्ग और उसके बाद चौथा शुद्र वर्ण का निर्माण किया गया। इस वर्ण व्यवस्था ने समाज में विभिन्न कार्यो का बटवारा कर के समाज को बंदिस्त बनाने का कार्य किया है। ब्राम्हणोने ज्ञान अध्ययन और अध्यापन का अधिकार आपने पास ही रखकर बाकी तीनो वर्गो को ज्ञान की पाबंदी लगा दी। इससे धर्मनीति का ज्ञान सिर्फ ब्राम्हणों के पास ही रह गया और ब्राम्हणों ने धर्म नीति से अपना कष्ट इस समाज व्यवस्था में सबसे उचा बाकी तिन वर्गो का अनपड और गुलाम बनाया। क्षत्रिय राजा भी ब्राम्हणों के अधिन रहे है । आपने राज्य कारभार चलाया करते थे और ज्ञान के बदौलत ब्राम्हण धर्मग्रंथों के सहारे राजा को आपने नीति के अनुसार राज्यकारभार का सलाह देते रहे। यही बात वैश्य, व्यापारी वर्गो के बारे में ही लागू रही है। इस वर्ण व्यवस्था में शुद्रो को पिढी दर पिढी सबसे निचला कद और कार्य दिया गया था। धर्म ग्रंथ की बाते सुनना भी उनके लिए धर्म को अपवित्र बनाने के बराबर था। ब्राम्हणों को छोड़कर तिनो वर्ण शिक्षा के पाबंदी के कारण ही गुलाम बने। इसके बारे में क्रांतिकारी ज्योतिराव फुले ने भी यह कहा था की ज्ञान के पाबंदी के कारण वंश ही देश के शुद्र और स्त्रिया अपनी गुलामी तोड़ नही सकते इस वर्ग व्यवस्था को और ज्ञान की पाबंदी हटाने का पहला प्रयास इस. पूर्व 255 वर्षे पहले ही तथागत भगवान बुद्ध ने सबके लिए ज्ञान सबको ज्ञान अर्जित करणे का अधिकार देने का विचार रखके ज्ञान मुक्ती और वर्ण व्यवस्था तोडने का आंदोलन बौद्ध धम्म के माध्यम से चलाया। इस आंदोलन का आसर इस देश में चारसों सालो तक रहा। बुद्धा का आंदोलन वर्ण व्यवस्था तोंड के सामंतवादी समाज व्यवस्था की स्थापना की और सभी को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनितीक अधिकार प्राप्त कर दिए। उस वक्त के उदा. के तौर पे देखा जाता है की, जंद राज घराने से सम्राट हर्षधर्वन तक शुद्र वर्णो के राजाओं ने चारसो साल तक राज किया तो दुसरी तरफ बहोत से शुद्र व्यापी और बौद्ध धम्म के धर्म प्रचारक बन गए। बौद्ध धम्म संस्कृती ने ज्ञान की पाबंदी हटाने से ही वर्ण व्यवस्था का खात्मा हो गया। इसी काल में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में किसी वर्णो के व्यक्ती को अध्ययन एवं अध्यापन करने का अधिकार प्राप्त किया। इस लिए बौद्ध धम्म यह ज्ञान मुक्ती का और ज्ञान की पाबंदी हटाने का देश का पहला आंदोलन माना जाता है। मगर यह क्रांति और व्यवस्था इस देश में सिर्फ चारसो साल चली उसके बाद इस क्रांति पर ब्राम्हणी व्यवस्था ने प्रतिक्रांति कराके फिरसे शुंगमित्र राजा के माध्यम से नयी व्यवस्था प्रस्थापित कि गई। यह व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के अधार पर ही बनकर इसको मनुस्मृती जैसे धार्मिक कानूनी ग्रंथ के द्वारा अनुशोषित बनाया गया। यह व्यवस्था जाति व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में ब्राम्हणों ने बहूसंख्य जातियों को कठोर ज्ञान की पाबंदी लगाकर हिन्दू धर्म के धार्मिक कानुन मनुस्मृती द्वारा मानसीक गुलाम, बनाया गया। यह इस की ज्ञान की पाबंदी का संघर्ष देश में बुद्धा के बाद भी चलता आया मगर ज्ञान की पाबंदी हटाने में सफलता प्राप्त नही हुआ। क्योंकि की ज्ञान के पाबंदी को धर्म का अधार प्राप्त था।

क्रांतिकारी ज्योतिराव फुले ने ख्रिश्चन और आंग्रेजो के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया और आधूनिक भारत के ज्ञान मुक्ती के आंदोलन की शुरुवात की उन्होंने दलित और स्त्रियों के लिए स्कूल बनावए और उनमें दलित और स्त्रियों को शिक्षा देणे का प्रयास किया। महात्मा फुले को आंदोलन से प्रभावित होकर राजर्षि शाहू महाराज ने बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को उच्च शिक्षा ग्रहण करणे में आर्थिक सहायता की और बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के दलित समाज के आंदोलन के लिए प्रेरित भी किया। यही आंदोलन बाबासाहेब इस देश की जाति व्यवस्था उद्धवस्थ करने के संघर्ष में तबदील कर दिया। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का संघर्ष इस देश के दलित, आदिवासीयों को सामाजिक न्याय और देश में जाति विहीन समता मुलक समाज के स्थापना किया। उन्होंने भारत को राज्य समाजवादी राष्ट्र निर्मिती का संघर्ष किया। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने इस आंदोलन के द्वारा दलित - आदिवासीयों को भारतीय संविधान के माध्यम से शिक्षा का अधिकार दिया। यह ज्ञान मुक्ती का ही संघर्ष था जो आज तक चल रहा है।

वर्तमान स्थिति में भी दलित - आदिवासी और ओबीसी को भी बेहत्तर शिक्षा से वंचित है। सवर्ण जातियों के छात्रों के बराबरी कि शिक्षा आज भी इन जातिओं के छात्र को प्राप्त नही होती हो। 1991 में देश भुमण्डलिकरण और निजीकरण का दौर शुरु हुआ और इस बिच बडे पैमाने पर निजी विद्यालयों और विश्वविद्यालय बनने लगे। भारतीय समाज की अर्थ व्यवस्था यह जाति व्यवस्था पर अधारीत होने के कारण ही सवर्ण जातियों भुमंडलीकरण और निजीकरण के दौर में पैमाने मे आर्थिक सबल बन गए। और इन्ही के ही छत्र नीजि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने लंगे, तो दूसरी तरफ दलित, आदिवासी जातियों जो

आर्थिक स्थिति से दुर्बल है इनके छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे सरकारी स्कूलों में ना तो शिक्षक छात्रो को पड़ा रहे है। ना कोई शिक्षा के साधन इन स्कूलो में है ना कोई कठोर शिक्षा नीति से इन छात्रों के लिए सरकार भी सरकारी स्कूलो, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को आधूनिक बनाने का प्रयास भी नही करती दिखाई दे रही है। नीजि स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इनके तूलना में यह आत्याधूनिक और आच्छे मामले में शिक्षा प्रदान करणे का कार्य कर रहे है। तो दूसरी तरफ दलित एवं आदिवासी छात्र जिस सरकारी स्कूलो में पढ़ रहे है उनको आठ्वी कक्षा तक ना कोई परिक्षा देते हुए पास करके दसवी कक्षा में फेल करने की व्यवस्था बनाई है। इससे दलित-आदिवासी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो रहा है। यह भी एक ज्ञान पाबंदी बर्करार रखने का तरिखा है। ज्ञान की जब तक पाबंदी है तब तक दलित- आदिवासी लोग गुलाम बनकर रहेगा। ज्ञानबंदी के कारण ही जाति व्यवस्था में दलित हजारों साल से शोषित और दमणकारी जिंदगी जिते आ रहा हैं। उन्हका शोषन हुआ है। समाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्तर पर इस देश के दलितों की गुलामी हिंदू धर्म के पवित्र आस्था जाति पर आधारीत है। जब तक जाति रहेगी तब तक दलित - आदिवासी शोषित और पिड़ित जिंदगी जिता रहेगा। वर्तमान स्थिति में और आझादी के 68 साल बाद भी दलित-आदिवासी एक स्वतंत्र जिंदगी जिने का प्रयास कर रहा है। मगर इस प्रयास को सवर्ण जातियोंने हिंसक संघर्ष में तबदील किया हैं। जब भी कोई दलित-आदिवासी विकास की ओर बढ़ने लगता है तब उसकी ओर सवर्ण जातियों उनके उपर अत्याचार दमन और शोषण करते हैं। उनके विकास प्रयास में बाधाए डालते हैं। आज भी देहातों में दलित महिलाओं के उपर सामुहिक बलात्कार, हत्याए, खेतो का नुकसान कराना घर जलाना, व्यक्ती को अपमानीत करने के शिलशिले रोज चलते हैं। इस भुमण्डलीकरण और निजीकरण के दौर में भी दलितों का आर्थिक स्थिती नही बदलती दिख रही हैं। आझादी के 68 साल बाद भी दलित गंदगी साफ करने का और निचली वर्ग का कार्य आपनी उपजिविका चलाना हेतू करता हैं। वर्तमान स्थिति तें ही देश के दलित झुग्गी-झोपड़ीयों और गंदी बस्तीयों में आपणी जिंदगी बिताते हैं।

जाति व्यवस्था ने ज्ञान और अर्थजन की पाबंदी डालकर दलितों को गुलाम और गरीबी की जिंदगी जिने के लिए मजबूर किया है। भुमण्डलीकरण और निजिकरण के दौर में सवर्ण जातियों ने अपने जाति के आधार पर बड़े पैमाने पर आर्थिक संपन्नता प्राप्तता को हासील करली है । और इसी जाति के आधार पर दलित लोगों को आर्थिक दृष्टी से कमजोर और बेबस बनाया है। भुमण्डलीकरण और निजिकरण का इस्तमाल तो देश के सवर्ण जातियों ने आपना फायदा और दलितों के शोषण के लिए ही किया है।

वर्तमान स्थिती में भी जाति व्यवस्था मजबूत दिखाई देती है। भूमण्डलीकरण और निजिकरण के दौर में भारतीय समाज व्यवस्था में कोई परिवर्तन नही दिखाई है। भुमण्डलीकरण और निजिकरण के दौर में भारतीय समाज व्यवस्था में कोई परिवर्तन नही दिखाई देता है। इसका एक कारण भी है, की सवर्ण जातियों अपने आर्थिक फायदों के लिए जाति व्यवस्था बरकार रखना चाहते है और दूसरा कारण इस देश में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों पर मानवतावादी और जाति विहीन समता मुलक जन आंदोलन खड़ा नही हुआ। पाश्चिमात्य देशों में समानता प्रस्थापित करनेवाले बड़े जनआंदोलन खड़े हूए उदा. के तौरपर देखा जाए तो आये एक कृष्ण वर्णिज्य लोगों को समानधारा में लाने के लिए सभी वंशो के लोगों ने मानवता के लिए और समानता के लिए आंदोलन चलाया मगर भारत में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों का जाति विहिन समाज निर्माण करणे का आंदोलन दलित ने कुछ हद तक चला रहे है। तो सर्वण जातियों ने इस आंदोलन का आज भी बडे पैमान पर विरोध दर्शाते है।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 1916 मे पहली बार कास्ट इन इंडिया इस शोध निबंध के दुनिया की सबसे भया वह भारत के दलितों की गुलामी रखी। भारतीय जाति व्यवस्था का दर्शन दुनियों के लोगों का दर्शया और भारत में इस गुलामी के ख़िलाफ एक बड़ा संघर्ष की सुरुवात की। देश में दलित - आदिवासीयों का शोषण जाति के व्यवस्था के अधारपर होता है, यह सिध्द करके उन्होने 1936 मे इंडियन इन कास्ट इस भाषण और ग्रंथ के द्वारा यह जाति व्यवस्था खत्म करने का मार्ग दिखाया Annihilation of caste's यह ग्रंथ इस देश की जाति व्यवस्था जड़से उखाडने का एक महत्वपूर्ण वैचारिक साधन हैं। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा था अगर जाति खत्म करने के लिए इस हिंदू धर्म की इस पवित्र आस्ता को खात्मा करना जरुरी है । ऐसी आस्था को खात्मा से ही देश में जाति विहिन समता मुलक समाज व्यवस्था प्रस्थापित हो सकती हैं। तो दूसरी तरफ बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर देश के सभी जातियों के लोगों को आर्थिक दृष्टी से समान अवसर देने का और देश को आर्थिक दृष्टी से मजबूत करने के लिए स्टेट इन मायनॉरिटीज यह ग्रंथ 1945 में लिख कर देश में राज्य समाजवादी राष्ट्र निर्मित का विचार रखा। और सभी को आर्थिक अधिकार समान रुप से प्राप्त होता हैं। आर्थिक विकास में एक समान अवसर प्राप्त होते हैं। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के इस देश में दलितों को जाति व्यवस्था के जंजीर से मुक्त करणे के लिए 1956 में नागपुर में बौद्ध धम्म की दिक्षा ली और हिन्दू धर्म का त्याग करके हिंदू धर्म की जातिय आस्था खत्म कर के समानतावादी व्यवस्था स्थापित करणे का सिलसिला शुरु किया था। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों के अधार पर नॅशनल एस.सी., एस.टी.,ओबीसी स्टूडेन्ट एण्ड यूथ फ्रन्ट (नसोसवायएफ) अपणा काम बढ़ाता जा रहा है।

इस देश के संविधान में सामाजिक रुप से पिछड़े हुए वर्गो को समान अवसर में लाने के लिए आरक्षण नीति आपना रहे है। बाबासाहेब ने कहा था जिस अधार पर देश के दलित-आदिवासियों की शोषण हुआ है, उसी अधार पर उनको समान अवसर आरक्षण के माध्यम से प्राप्त होन चाहिए। किन्तू बाबासाहेब ने जातिगत और धर्म के आधर पर आरक्षण देणे का विरोध जानते हुए भारतीय समाज के दलित जाति को अनुसूचित जाति और देश के आदिवासी जाति के लिए अनुसूचित जनजाति इस शब्द का प्रयोग किया याने की जाति को बढ़ावा ना मिलते मंगर आरक्षण के आवसर सिर्फ सरकारी शिक्षा संस्थान और नौकरीयों में ही होने के कारण निजि शिक्षा संस्थान और निजि क्षेत्र में दलित आदिवासियों की भागीदारी नही के बराबर हैं। आज के भुमण्डलीकरण एवं निजिकरण के दौर में सरकारी क्षेत्र को तेजी से निजि क्षेत्र में तब्दील किया जा रहा है। इससे जो सरकारी क्षेत्र में आरक्षण के माध्यम से शिक्षा का और नौकरियों का जो अवसर मिल रहा था वह खत्म हो रहा हैं। अगर देश में निजि क्षेत्र में दलित-आदिवासियों को आरक्षण नही मिलता है तो दलितो की आर्थिक और सामाजिक स्थिती दर्दनाक बनेगी क्योंकि देश की समाज व्यवस्था जाति व्यवस्था पर आधरित है। और देश के सभी निजि क्षेत्र सर्वण जातियों के अधीन है । सर्वण जातियों देश के दलित-आदिवासियों को समान अवसर नही देना चाहते हैं। यह एक भयावह परिस्थिती है इसको नकारा नही जा सकता। इन्ही सभी समस्याओं को लेकर और बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों को नए समाज निर्माण का आधार मानकर नेशलन एस.सी., एस. टी., ओबीसी एण्ड यूथ फ्रन्ट (नसोसवायएफ) देश के शोषित, पिड़ित, आत्याचरी दलित आदिवासी ओबीसी छात्रों को संगठीत करणे का कार्य कर रहा है। इस देश में दलित, आदिवासियों को समान और आनिवार्य शिक्षा नीति लागू करे दलित आदिवासीयों के लिए नीजि क्षेत्र में आरक्षण कानून सैना, न्याय पालिका में आरक्षण, देश के सभी जिली में दलित, आदिवासी छात्रों के लिए पूर्ण सुविधा संपन्न एक हजार छात्रों के लिए छात्रावास की स्थापना यह मुख्ये माँगे लेकर हम पिछले कई सालो से जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे है।

जिनके खुन में विद्रोह पनपता हैं ऐसे यूवा छात्रों को नसोसवायएफ एक बड़े संघर्ष और क्रांति के लिए संगठीत कर रहे है। आप सभी छात्र और यूवाओं को अपील हैं, हम गुलाम हैं मगर आनेवाले हमारे नस्लों (पिढी) को आज़ादी की जिंदगी देने के लिए यह संघर्ष मिल के करे और आज ही नेशनल एस.सी.,एस.टी., ओबीसी एण्ड यूथ फ्रन्ट (नसोसवायएफ) के सदस्य बने।

जय भीम
नबो बुद्धाय

– डी. हर्षवर्धन
राष्ट्रीय अध्यक्ष
नसोसवायएफ

नेपाल के दलितों के आरक्षण की मांग

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद डॉ. उदित राज ने कहा कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तरह ही नेपाल में दलितों- आदिवसी, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। श्री विश्वेंद्र पासवान के नेतृत्व में नेपाल में दलित आंदोलन चल रहा है। उनकी मांग है की संविधान में आरक्षण में आरक्षण शामिल किया जाए। वर्तमान में नेपाल संविधान सभा के द्वारा मसोदा तया किया जा रहा है। पासवान जी डॉ. उदित राज के संपर्क में लगातार रहे है और नेपाल की दलितो की तरफ समर्थन हासिल करने की अपील भी की। डॉ. उदित राज नेपाल के दलितो की दुर्दशा के बारे में अवगत है। अनुसूचित जाति/जनजाति परिसंघ जो-शोर से नेपाल के दलितो का समर्थन करता है।

श्री बाबुराम भट्टारार्य (यूनाइटेड पार्टी ऑफ नेपाल) से डॉ. उदित राज जी ने इस संदर्भ में संपर्क किया और भट्टराई जी ने कहा कि हम इस आरक्षण को समर्थन करते है। सवाल यह है कि नेपाल काँग्रसे पार्टी और कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्कसिस्ट लेनिनिस्ट) का संविधान सभा में बहुमत है, इसलिए हमारी पार्टी आरक्षण को संविधान में शामिल कराने में असक्षम है।

कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्कसिस्ट लेनिनिस्ट) के संबंध भारत के कम्युनिश्ट पार्टी मार्कसिस्ट (सीपीएम) से अच्छे बताए जाते है। डॉ. उदित राज ने सीपीएम के महासचिव सीताराम येचूरी से संपर्क करने की कोशिश की, कि वह कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेतावों से संपर्क करके यह बताए कि जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए वह भी संविधान में आरक्षण के प्रावधान में समर्थन में आए।

सामाजिक समानता कायम रहे इसके लिए यह अनिवार्य है कि भारतीय संविधान सम्मत विधानों के तहत नेपाल में भी वंचित समुदाय के हितो का सरक्षण प्रदान की जाए। हमारा देश भारत दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा शक्ति होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम माननीय विश्वेन्द्रमान पासवान जी के मुहिम को खुलकर समर्थन दे जिससे कि दक्षिण एशिया में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी का मार्ग प्रसस्त है और नेपाल में लोकतन्त्र कायम हो। इसमें भारत का अतुलनीय योगदान है इस लिहाज से भी भारत की सामाजिक न्याय समर्थक ताकतों को नेपाली वंचित जनमानस को उनके अधिकारो को दिलाने हेतू पूर्ण सहयोग देना चाहिए

– डॉ. उदित राज
सांसद एवं
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अनुसूचित जाति/ जन
जाति संगठनों का अखिल भारतीय
परिसंघ

परिसंघ एवं नसोसवायएफ का पाली राजस्थान में सम्मेलन

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज जी का अभिनंदन एवं दलित जागृति सम्मेलन जन समूह में नगर परिषद पाली के सभागार में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाबासाहेब की प्रतिमा के समाने दीप प्रज्वलन व मालार्पण के साथ भगवान बुध्द की वंदना से हुई।

उन्होंने कहा कि परिसंघ ही देश के दलितों व आदिवासियों की बड़ी ताकत है। अगर दलित एक नहीं हुये तो उनके अधिकार छीन लिए जाएगें। उन्होंने सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों से कहा कि उनको आरक्षण की बदौलत ही नौकरी का पद मिला है। उनपर बबासाहेब अम्बेडकर का कर्ज है, तथा इस कर्ज को उनको हर हाल में चुकता करना हैं। उन्होंने दलित-आदिलवासी युवाओं से परिसंघ से जुडकर दलित अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार रहने का आव्हान किया। उन्होंने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि दलित पर होने वाले अत्याचारों को उसे खुद ही खत्म करना होगा। उन्होंने अत्याचार करने वालो के खिलाफ अपने स्तर पर ही लड़ाई लड़ने का आव्हान करते हुए कहा कि जब हम अत्याचार सहन करना छोड देंगे तो अत्याचार अपने आप ही खत्म ही जाऐगा। इसके लिए दलित समाज को एक जुट होकर अत्याचार के खिलाफ लड़ना होगा। दलित समाज में गली-गली और छोटे-छोटे संगठन हैं, जो दलित समाज के लिए बहुत घातक बनते जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन अपनी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है ना की जातिवाद फैलाने के लिए है। उन्होंने बताया कि डॉ. अम्बेडकर की सोच पर देश चलता तो भारत कभी का महा शक्ति बन जाता।

डॉ.उदित राज ने आगे कहा की अम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में महिलाओं को सम्पति में बराबर का हिस्सा देने का मुद्दा संसद में उठाया था। यदि यह उस समय लागू हो जाता तो आज देश में महिलाओं पर हो रहे आत्याचारों की संख्या वर्तमान से काफी कम होती।

नसोसवायएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. हर्षवर्धन ने अपने सम्बोधन में दलित-आदिवासी के युवाओं को एक जुट होकर संगठित होने के साथ आगे आने को कहा। साथ ही उन्होंने दलितों को अपने स्वतंत्र अधिकारों का उपयोग करने की बात की। उन्होंने कहा कि दलित-आदिवासी यदि संगठित हो जाएगें तो अत्याचर अपने आप ही खत्म हो जाएगा।

परिसंघ ईकाई पाली के जिलाध्यक्ष मोहन लाला रासू ने अतिथीयों को स्वागत करने के साथ-साथ अपने सम्बोधन में सभी से बाबासाहेब अम्बेडकर के बताए मार्गो पर चलने की सीख दी।

मुख्य अतिथि डॉ. उदित राज जी पाली में डॉ. अम्बेडकर भवन में अशोका का पेड़ लगाकर वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जेठमल डागा, कन्हैयालाल परिहार, गोवर्धन सिंघडिया, नथराम मीणा, नसोसवायएफ के राज्य समन्वयक अशोक कुमार सिराण, लक्ष्मण मीणा, अम्बालाल वागोरिया, नरसिंग मुछावत, भीमराम, मदन तेजी, कताराम आदिवाल, मांगीलाल चौहान, विश्राम मीणा, ओ.पी. जयपाल, कोटा से लेखराज, चिंरजी लाल, पन्नालाल रैंगर, पेमाराम मीण्डावत, विक्रम पंवार, चतराम नेतरा, राकेश माटी, लच्छाराम बाघेला, भंवर लाल बरासा आदि कई कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा।

– मोहन लाल रासू
जिला अध्यक्ष परिसंघ

माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत विशाल माला एवं शॉल के साथ किया गया। डॉ. उदित राज ने कहा कि परिसंघ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर परिसंघ का आंदोलन या सांसद के बीच किसी खास मजबूरी या समाज हित में चुनाव करना हो तो डॉ. उदित राज सांसदी छोड देगें। उन्होंने कहा कि परिसंघ को उन्होंने बड़ी मेहनत से सींचा हैं।

SC/ST/OBC Confederation organises Yoga

Jammu 21.06.2015 Today is a International Yoga day & our Prime Minister Shri Narendera Modi has given a call to practice Yoga to make onesely fit sound and medicine free. On this thought of our Prime Minister, cadre of State unit of All India Confederation of SC ST OBC Organisations assembled at Baba Sahib Dr B R Ambedkar Chowk Gandhi Nagar Jammu and performs various asanas of Yoga. While addressing the participants, State President Confederation Shri. R. K. Kalsotra said that Yoga is more beneficial to the poor masses of the society as it not need money & in infrashichne, we can perform it in open space and without spending any money on it. Yoga keeps us healthy, strong and flexible to keep our day to day work efficiently as said by our Prime Minister Sh Modi Ji and Confederation fully support the new idea of his to make the country as well world free of illness.Let every body join Yoga anbd take pledge to practice Yoga everyday for a better physical, mental and good health. Other prominent leadexs who joined at Ambedkar Chowk in Yoga were Addl Advocate General Bharat Singh Jamwal, Adv Shah Mohd, Ramesh Sarmal, Yousaf Malik, Harbans Lal, Javid Watal, Dr Viney Kumar,Dr Ramesh Kaith, Eng Jsgdish Raj, Shashi Sayal , pyar chand & other

INDIA NEEDS DRASTIC CHANGES

People get excited and become optimists whenever they start the process of change in leadership and renaissance. But with the passage of time, criticism begins. People expect the Government to accomplish a certain task. Our society is more self-centric than community-based. Therefore, it is always ready to do anything for personal gains. To clean up the nation, the Prime Minister launched Swatch Bharat (Clean India) campaign on 2nd October, 2014 and appealed not to connect this movement with any Party so that people may not link this campaign as politically influenced and make our country spick and span like other countries of the world. He made an unprecedented beginning by taking the broom in his own hands. There went a message that cleaning is not a mean work. Despite that the countrymen did not make this campaign a part of their life as they should have.

Recently I got an opportunity to address the Indian Diaspora in a fine evening in Australian city, Sydney. During question-answer session a gentleman asked what Modi ji has done when there is still garbage in India. Since I was bound to give reply, I asked him despite having such a mammoth education system in India comprising of hundreds of universities, lakhs of colleges and schools coupled with innumerable number of writers, journalists, intellectuals and researchers, the system could not teach them a very small lesson of cleanliness. Then it is the system which is to be blamed and not the Prime Minister. Was there any need for the Prime Minister to appeal for cleanliness? Had our education system accomplished this task, we could have utilized this time and resources in some other fruitful channel. My reply made that gentleman unanswerable. He should have rather thanked the Prime Minister for his initiative instead of criticizing him and his initiative.

Government job seems to be lucrative one and everybody tries to get it by spoil their youth. On the other hand they have scant regard for doing jobs in Government hospitals, railways, buses, etc., and shirk their official duties. Employees and officers irked when the Central Government started the process of biometrics to observe punctuality in offices. Many of them started feeling pain in their personal lives when their habit of coming late and leaving the office early got challenged. Government did bear the brunt in Delhi's Assembly elections because of this initiative. Why a Doctor, an engineer or a business manager who could earn crores of rupees in public life, preferred to enter bureaucracy? After all, what is the reason? In Government job you have to work less. Come late and go early! The merry goes round! There is more profit in creamy departments. It is better to understand in inklings lest the truth should sometimes be bitter.

Our Indian society has inculcated a psyche that Government should do everything. The question here arises that what the Government is? It is made by the people and run by the people. Representatives of the people can only lead the public. But it is the people who observe the law and order and follow Government policies and programmes. There can be a sea change in India if programmes like Swatch Bharat, Make in India, Digital India, Sansad Aadarsh Gram Yojna, Jan Dhan Yojna, Skill India, etc. are implemented ipso facto. This drastic change can come in India as it has come in other foreign countries from time to time. Without people's cooperation it is not possible.

Despite resources, favourable climate, fertile land, there cannot be any development without people's cooperation. Only the citizens of the country can give maximum contribution in its development and a good society. The condition of countries like New Zealand and Australia is not so congenial but they have well established themselves in the world. In the 1770s convicts from England and Europe were left there as a measure of punishment. What height they have achieved in around 200 years is not difficult to know. We could not take our country to that height even in 5,000 years. Some people may give an excuse of our population as the main reason behind our failure. Then there is answer to their argument also by citing the example of Japan and Korea where population is quite dense, land is not smooth and you see mountains and mountains all around. Even then their achievements are not hidden from anybody. Citizens make the nation.

There is need of a revolution in India and that too in the social segment. Like the era of renaissance in Europe between the 14th and 17th centuries which gave a fillip to scientific thinking, the same renaissance is needed in India. This renaissance which was born in Italy engulfed the whole of Europe. Europe also witnessed yet another revolution in the 16th century which was known as Puritanism. Japan was cut off from other communities of the world till 1860 and it may be presumed she would have remained deprived of knowledge, science and technology. But Meji Revolution changed Japan. GDP of Japan between 1868 and 1872 was 1,026 tone and exports 646. That increased to 12,460 tones and 9,462 between 1909 and 1914. American progress was also behind Maji Revolution. When Japanese came to know of American's development, they started to compete with each other and readied for any sacrifice. Meji means astute administration and a mixture of modernization with ancient and traditional values. Likewise the Cultural Revolution in China in 1966 contributed a lot in psychological change of its people notwithstanding the fact that political power was misused.

India can witness a big revolution if the programmes of the Government are implemented in letter and spirit. Governments hardly take revolutionary steps. That is why this campaign is appreciable. People can initiate steps aimed at development and revolution. Campaigns like Swatch Bharat should have been launched by the people but the Government came forward to do so. If the people do not participate in the programme it would be a historic error. I appeal to the people not to take my views as politically motivated because I am also a BJP Member of Parliament.

- Dr. Udit Raj,
Member of Parliament &
National Chairman,
All India Confederation of
SC/ST Organizations

Importance of Buddhist Philosophy

Lord Buddha was born in the year 563 B.C. and breathed his last in the year 483 B.C. He attained Enlightenment in the year 528 B.C. His Birth, Enlightenment and Mahaparivirvan all took place on Baisakhi Purnima day in different years.At the time of birth, he was given the name of Siddharth Gautam. He was borth with a silver spoon in his mouth because he was born in a royal family. His parents and other family members came to know about his total lack of interest in the worldly affairs, they would provide him more and more material comforts but these did not attract him any more and he decided to renounce his family life and devote his time for the welfare of humanity.From the childhood, he was a peace loving boy. Despite being born in a royal family, worldly possessions could not impress him much. He often used to become restless on seeing sorrows and sadness all around. He was married to a lady named Yashodhra and they were blessed with a son. From the very childhood, he had no interest in affairs of the royalty. As and when, his According to tradition, for the service of humanity and spiritual attainment, people used to renounce the world and do penance in a secluded place. He, therefore, did penance for six years along with five other persons. The penance was so severe that physically he became extremely incapacitated. After some time, he realized that in this way, it was not possible to do service to the humanity. He further realized that even if he was able to control his senses after doing so much of penance, the society will not stand to gain in any way. Of course, by doing meditation in an isolated place, one could gain insight into some basic aspects of life but this also gives a message of become dependent on others. Whether penance is done in a deep forest or elsewhere, one needs basic necessities of life like food and clothes etc. Somebody makes these things. The people who create these basic necessities of life would start thinking that family life has no significance and the path of renunciation is the best way which had a negative impact on the society and the concept of work culture got a big set-back. By social isolation, one cannot solve the problems of the society. Gradually he started realizing the futility of doing meditation in isolation and finally he left the forest after leaving his colleagues there. During his travel, he got Enlightenment in Gaya, Bihar, under a Peepul tree that Middle Path is the best way to end the sorrows of the world. This is how he got Enlightenment. He delivered his first discourse to the same five persons whom he had left behind in the forest. As soon as these five persons at Sarnath saw Siddharth Gautam coming towards them, they thought that he would admonish them as they had left him in the forest but what happened really was just the opposite. As soon as Siddharth Gautam appeared on the scene, they were greatly impressed by him and got Deeksha from him. It is evident from this fact that nothing much can be achieved by remaining isolated from the society.

The four eternal truths as propounded by Lord Buddha are as relevant today as they were at that time. The first eternal truth was that this World is full of sorrows. If there is sorrow, there has to be a reason for that also. If there is a reason, there has to be a solution for that also. This was the third eternal truth. The fourth eternal truth is the 8-fold path. Lord Buddha had understood the laws of nature very deeply and adopted them in the life of human beings. In today's modern world, people are fed up with corruption, poverty, casteism, communalism and unemployment. There must be some reason for this situation. If man understands the reason for this sorrow, the solution is possible. Most of the people are very unhappy but they really do not understand the reason for this unhappiness. People who have been suffering for thousands of years from the evils of untouchability and exploitation, attribute their suffering to the past karmas of their previous births and even now think so when actually there is no truth in it. If there is any disharmony in the society, there are some selfish and mischievous people behind this situation. Thus there is definite some reason for every sorrow. In a way, this is a scientific approach to problems. We can put an end to the sorrows of the world if we adopt the 8-fold path in our day-to-day life. The 8-fold path means right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration. According to Lord Buddha, for this purpose, no Guru or hear-say discourse is required. Every individual is his own master. He is the sum total of his actions rather than any divine intervention or any other reason.

There is a reason for the present day corruption. If people can be made to understand that happiness and peace cannot be achieved by too much of indulgence, then we can get rid of corruption. No other movement could fight so strongly against casteism as has been done by the scientific and humanitarian philosophy of Lord Buddha. For thousands of years, Buddhism was prevalent throughout the length and breadth of India but finally its goodness became its weakness. The quantum of emphasis that Buddhism laid on non-violence cannot perhaps be found in any other religion, philosophy or concept. Of course this was its weakness and another major reason for its downfall was the conspiracy hatched by the followers of the caste system. A statute of Lord Buddha was demolished, yet there was no violence on this account in any Buddhist country. Dr. Ambedkar again revived Buddhism in India. On the 4th November, 2001, the All India Confederation of SC/ST Organizations served the cause of by converting lakhs of people to Buddhism. Followers of Buddhism are so peaceful that Bodh Gaya, which is the place where Lord Buddha got Enlightenment is under the control of Hindus and not Buddhists. The world has never faced such a serious and heinous problem nor will it ever face in future as the problem of caste system faced by India. Main reason for India's slavery for thousands of years has been the fact that we were divided into small groups because of the caste-system. Administration has been greatly influenced by caste factor rather than by development and progress. Buddhism is a powerful tool to fight against caste system and it has done in the past also. It is most the Dalits who follow Buddhism in the country even though Lord Buddha was born in an upper caste family. Even today you will not come across a single instance where an intellectual, religious guru, political leader or a social activist born in a Dalit family finds a place in an upper caste house. This is a major difference in the mind-set of Dalits and upper caste people.

+++

Dr B. R. Ambedkar 124th Birthday Celebration in Karnataka

Celebrating Dr B.R Ambedkar 124th Birthday Celebration on Sunday 05.07.2015 at Jai Bheem Bhavan Bengaluru from our All India SC/ST Organizations Karnataka State Unit.

Programme inaugurated by Smt.Dr.Samatha Deshmane Prof of Sociology Dept. Bengaluru University, Chief Guest Smt.Dr BT Lalit Nayak famous author and Ex Minister Govt of Karnataka & Sri Purushottam Dassji Canara Bank SC/ST Employees welfare association,State Convenor of AICSO, Sri K.D Nayak Legal Advisor of Govt of Karnataka, V Bhaskar Roa all India Defence Organising Secretary & State president Sri J Srinivasulu & State General Secretary channappa presented at the event.

Dr. Ambedkar Jayanit Celebrated at Bangalore.

At the same time we had distributed free school bags to poor Children's of slum wards.

Sri Purushottam Dass is happy to say that this is first time celebrating from the All India Confederation of SC/ST Organizations Karnataka distributed school bags for poor children's & education for women. B.T Lalita Nayak Said Fill up the backlog SC/ST Posts to all concerndept we pressurized the Govt of the Karnataka & Govt is not providing to B.B.M.P Contract labours safety aspectus we had approached to BBMP wards & also provide the basic necessity of increasing the salary & ESI,PF etc.

Smt.Dr.Samatha Deshmane said : Dr Udit Raj has given a wonderful support to Karnataka State Unit & our office bearers of organizations has to utilize proper way serve the people & unity is the strength in the organization. And Dr Udit Raj is our man serving to our community people like Dr.Ambedkar's facilities of the constitution.

- Channappa
State Gen. Sec/AICSO.
Karnataka Unit.

+++

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 16 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 July, 2015

CONFERENCE IN PALI (RAJASTHAN)

Pali (Rajasthan) July 12, 2015: Under the auspices of All India Confederation of SC/ST Organizations, Awareness cum Welcome Conference was held on Sunday, July 12, 2015 in the Municipal Corporation Auditorium at Pali in Rajasthan. Dr. Udit Raj, Member of Parliament participated in the Sammelan. In the very beginning, he garlanded the statue of Baba Saheb, Dr. B.R. Ambedkar by lighting of the lamp and with the invocation to Lord Budhha.

Dr. Udit Raj was also welcomed by presenting a shawl and mammoth garland. He told the audience that the Confederation is the real force behind them. If under any compulsion or in the interest society and country, he is to choose between the Confederation and Member of Parliament, he will sacrifice the latter. He informed that he has fostered the Confederation by the dint of hard work. He further said that Confederation is the real strength of Dalits and Adivasis of the country. If

Volunteers Attending Conference

Dalits are not united they will lose their hard-earned rights. He called upon the Government officers and employees that it is because of the reservation policy that they could get Government jobs. It is their debt to Baba Saheb Ambedkar and they have to pay back this debt. He also urged upon the youths to join their hands with the Confederation and be ready to wage a war for the for the rights. He said to put an end to the atrocities against the Dalits, only Dalits will have to fight against these atrocities. By calling upon Dalits he said when we stop tolerating atrocities against the Dalits, the atrocities would end automatically. There are pocket organization in every hook and corner which are detrimental. He said Associations are made for our social security and not for spreading casteism and meeting or mind food. Carrying forward his address, Dr. Udit Raj said Dr. BR Ambedkar was the first such person who raised the issue of equal property rights for women in Parliament. Had it been put to practice at that time, the number of atrocities against women would have fallen.

D.Harshavardhan, National President of National SC, ST, OBC Student & Youth Front, in his address to the audience, called upon the Dalit-Adivasi youths to get united and come forward. Simultaneously he asked the Dalits to utilize their fundamental rights. He reiterated the fact that if Dalits get united, atrocities against them would end on their own.

Shri Mohan Lal Sasu, District President of Pali Unit of the Confederation, while welcoming the guests, called upon them to follow the path shown by Dr. B.R. Ambedkar.

Chief Guest Dr. Udit Raj also planted Ashoka tree at Dr. Ambedkar Bhawan.

S/Shri Jethmal Daga, ,Kanheya Lal Parihar, Goverdhan Singhadia, Nathram Meena, State Coordinator of National SC, ST, OBC Student & Youth Front Ashok Kumar Siran, Laxman Meena, Ambalal Vagoria, Narsing Muchhawat, Bhimram, Madan Teji, Kataram Dadiwal, Mangilal Chauhan, Vishram Meena, O.P. Jaipal, Lakhraj from Kota, Chitraunji Lal, Pannalal Raiger, Pemaram Meedavat, Vikram Panwar, Charam Netra, Rakesh Mati, Lachharam Baghela, Bhanwar Lal Bawal, et al, who were prominent guests at the event, contributed their lot for the success of the Samelan.

- Mohan Rasu
District President

✦✦✦

TIME TO FORGET DIFFERENCES AND WORK TOGETHER

Indians in Australia should forget their differences and work together as one entity for their betterment in Australia, according to Dr Udit Raj, MP from North West Delhi Parliamentary constituency. Speaking to a gathering of BJP supporters and media, Dr Raj who is on a personal visit to Australia, praised the work done by OFBJP in bringing the community together.

Dr Raj said "I've heard there's a lot of infighting in the community in some cities. This infighting is not going to take us anywhere as a minority group. We need to dedicate our time to work together and improve our standing in the wider Australian community." Dr Raj represents a constituency in Delhi that has over 5 million residents. The dinner was hosted by OFBJP Australia and Festivals of South Asia (FOSAI) jointly at Food Sutra.

Talking about his travels through Victoria, Dr Raj said: "I was quite pleased to see the standard of living in the country side here. If Australia can have such quality of life in the country, India should bring the same quality of life to our villages. There's a lot we can learn from each other and this is one area where there can be collaboration."

On Smart City projects in India, Dr Raj said: "Smart Cities are not left to one builder alone. It is done by consortiums and we request Australians to come forward to contribute to the development of smart cities."

Miss. Sema Raj & Dr. Udit raj at Melbourne, Australia

Emphasising the importance of being loyal to Australia, Dr Raj said: "Your first love and sense of loyalty should always be with Australia. But you also have a duty to contribute to the growth of India." I call up on Indians in Australia to contribute to Swachh Bharat," added Dr Raj who is travelling with his wife Seema Raj, the Income Tax Commissioner in Delhi. Dr Raj also praised former Victorian Premier Mr Ted Baillieu and hoped that someday the Australian government will have Baillieu as the Ambassador to India.

Dr Raj wished Raashi Kapoor luck for the upcoming Miss Australia Pageant before concluding his remarks. In his remarks to the gathering, Vijeth Shetty from OFBJP said: "Indians in Australia have great quality of life where we have spare time in hand. We must contribute at least 10 per cent of our time to community work. Shetty also added that OF BJP will lobby the Federal government to ease visa rules for Indians to work in Australia.

Hari Yellina from FOSAI thanked Dr Raj and Seema Raj for making time to address the gathering. Yellina said: "FOSAI has worked on building a very solid cultural foundation for the Indian community in Australia through festivals. We want to work towards giving an opportunity for Indians living in Australia to experience the magic of festivals of India. Through Festivals we can also promote Indian culture to the wider Australian community."

Siddharth Suresh from The Indian Sun said: "Members of the OFBJP have selflessly promoted the cause of Indians in Australia and have ensured that there is less infighting between various groups working to represent Indians. They have acted as a group that binds various cultural, religious and political groups for one cause."

Ashwin Pareek Bora, Shivesh Pandey, Prajesh Goswami and Amith Karnath from OFBJP were present at the function. Former adviser to Victorian Premier Nitin Gupta, Sarika Prakash from FOSAI and Srikanth Balan from The Indian Sun also attended the event.

- Courtesy The India sun

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: aicscst@gmail.com
Computer typesetting by Ganesh Yerekar